भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 239*

(19 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पंजाब को ग्रामीण विकास निधि

***239. श्री सुशील कुमार रिंकू:**
श्री जसबीर सिंह गिल:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब सहित देश भर में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब में इनमें से प्रत्येक योजना के लिए संस्वीकृत और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पंजाब को ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी न किए जाने की जानकारी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) पंजाब के लिए ग्रामीण विकास निधि की कितनी राशि बकाया है और सरकार रोकी गई ग्रामीण विकास निधि पंजाब को कब तक जारी करेगी; और

(ङ) सरकार द्वारा पंजाब के लिए ग्रामीण विकास निधि में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इसे कब तक बढ़ाए जाने की संभावना है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय पंजाब राज्य सहित देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) जैसी कई योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। तथापि फरवरी, 2016 में शुरु किए गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को 31 मार्च, 2022 से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्षा सिंचित/खराब भूमि में सुधार लाने के लिए भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का भी कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख): पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में इनमें से प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत और आवंटित निधियों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग) से (ङ): जहां तक ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) जारी न करने का सवाल है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सूचित किया है कि मामला वर्तमान में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, ग्रामीण विकास के लिए निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों के पास शेष उपलब्ध निधियों, योजनाबद्ध आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक दस्तावेज/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने, इन योजनाओं के तहत पहले से आवंटित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने, योजनाबद्ध दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक आवश्यकता के आकलन को ध्यान में रखते हुए निधियां जारी की जाती हैं। ग्रामीण विकास की योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहता है और जहां कहीं संभव हो, पंजाब राज्य सहित अन्य राज्यों के आवंटन को बढ़ाता है।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 19.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 239 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान पंजाब के भीतर इनमें से प्रत्येक योजना के लिए स्वीकृत और आवंटित निधियों का ब्यौरा

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	जारी निधि
2022-23	1194.49
2023-24 (14.12.23 की स्थिति के अनुसार)	877.58

2. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय रिलीज
2022-23	71.68
2023-24 (14.12.23 की स्थिति के अनुसार)	17.28

3. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	जारी की गई निधियां	राज्यांश सहित व्यय
2022-23	231.063	428.72
2023-24 (14.12.2023 की स्थिति के अनुसार)	215.10	423.41

4. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

(लाख रुपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
2022-23	4644.38	3483.28
2023-24	2644.28	2322.19 (नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार)

5. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

(लाख रूपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय रिलीज
2022-23	164.89
2023-24 (वर्तमान की स्थिति के अनुसार)	16.43

(स्रोत:-डीडीयू-जीकेवाई के तहत दर्ज सूचना)

6. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

(लाख रूपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय रिलीज
2022-23	966.27
2023-24 (आज की स्थिति के अनुसार)	361.67

(स्रोत:- आरएसईटीआई के अंतर्गत दर्ज सूचना)

7. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय रिलीज
2022-23	0.00
2023-24 (13.12.2023 की स्थिति के अनुसार)	13.07

8. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	केंद्रीय रिलीज
2022-23	33.90839
2023-24	--

9. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी)

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	संभावित आवंटन	केंद्रीय रिलीज
2022-23	15.17	5.300
2023-24	12.93	3.230

******